

उपायुक्त का न्यायालय

पी० डी० एस० अनुज्ञप्ति रद्द वाद सं०-०६/२०१५

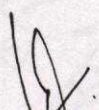
हाजरा खातून-बनाम-राज्य

अभिलेख उस्थापित। यह वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया के ज्ञापांक-४४० दिनांक-२१.१०.२०१३ द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रथम पक्ष हाजरा खातून पति-मो० ताहिर अंसारी के अपील पर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। वाद का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है:- ग्राम-नावाडीह प्रखण्ड-सरिया के अन्तर्गत दिनांक-०२.०९.२००८ को जनवितरण प्रणाली से संबंधित अनुज्ञप्ति सं०-१३/२०१० १५ पन्द्रह सदस्यीय महिला समूह को जारी किया गया। उल्लेखनिय है कि उक्त महिला सामूहिक जनवितरण प्रणाली, नावाडीह का अध्यक्ष मसो० पूनम पति-स्व० नरेश गिरि एवं सचिव हाजरा खातून पति-ताहिर अंसारी है। प्रखण्ड अपूर्ति पदाधिकारी सरिया एवं संबंधित पंचात के पंचायत सेवक के प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया ने उक्त समूह के जन वितरण प्रणाली का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया। अनुज्ञप्ति रद्द होने के उपरान्त प्रथम पक्ष द्वारा इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है। उक्त के संबंध में प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का निम्न अभिकथन है:-

१. यह कि अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सरिया के प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया है कि समूह के कतिपय सदस्यों का नाम बी०पी० एल० में दर्ज नहीं है। परन्तु अनुज्ञप्ति निर्गत करने के समय इस बात का जिक्र नहीं किया गया।
२. यह कि माननीय अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया ने अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व उक्त समूह के सदस्यों को अपन पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया।
३. यह कि प्रश्नगत महिला सामूहिक जनवितरण प्रणाली, नावाडीह के सभी सदस्यों में अधिक संख्या में सदस्य बी० पी० एल० धारी सदस्य है।
४. यह कि किसी भी अनुज्ञप्ति को उसी परिस्थिति में रद्द किया जा सकता है जब Control Order में निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अनुज्ञप्ति के निर्धारित शर्तों का उल्लंघन हुआ हो।

प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तर्क, सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलील एवं सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट होता है:-

1. यह कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सरिया एवं पंचायत सेवक के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि महिला सामूहिक जनवितरण प्रणाली, नावाडीह का 15 सदस्यों में से मात्र आठ सदस्यों का ही बी० पी० एल० सूची में नाम दर्ज है। विभागीय संकल्प सं०-1580 दिनांक-06.08.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी भी जनवितरण प्रणाली समूह का कतिपय सदस्यों का नाम बी०पी० एल० सूची में दर्ज नहीं होने की स्थिति में समूह का गठन अपूर्ण रहता है। इस परिस्थिति में अनुज्ञप्ति निर्गत करना नियमों के विरुद्ध है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि पंचायत सेवक के दिनांक-14.07.2014 जाँच प्रतिवेदन में पाया गया है कि उक्त महिला सामूहिक जन वितरण प्रणाली, नावाडीह का अध्यक्ष मसो० पूनम पति-स्व० नरेश गिरि का नाम बी० पी० एल सूचीमें दर्ज नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया द्वारा उक्त जन वितरण प्रणाली का अनुज्ञप्ति को रद्द करने संबंधी आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है।
2. अभिलेखबद्ध पंचायत सेवक, नावाडीह पंचायत एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संबंधित जन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जनवितरण प्रणाली के तहत सामाग्री के उठाव के पश्चात सामाग्री का वितरण ग्रामीणों के बीच नहीं किया जाता है एवं ग्रामीणों के द्वारा लिखित व्यान देकर उक्त जन वितरण प्रणाली के सचिव हाजरा खातून के पति मो० ताहिर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त आरोप के संदर्भ में उक्त जन वितरण प्रणाली के अध्यक्ष एवं सचिव से स्पष्टीकरण की मांग की गई परन्तु संबंधित अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की प्रति न तो प्रथम पक्ष के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया न ही अभिलेख के साथ संलग्न है।
3. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निम्न आरोप है-
(क) नावाडीह S.H.G समूह के सचिव हाजरा खातून द्वारा समूहिक हित के इतर व्यक्तिगत हित के लिए जन वितरण प्रमाणी का संचालन कर रहे हैं।



(ख) सचिव हजारा खातून अपने पति मो० ताहीर अंसारी के माध्यम से नावाडीह S.H.G समूह का संचालन किया करते है जो नियमों का उल्लंघन है।

उक्त आरोप के संदर्भ में प्रथम पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का तर्क/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आदेश

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ,बगोदर सरिया द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए महिला सामूहिक जनवितरण प्रणाली,नावाडीह के पक्ष में दिनांक-02.09.2008 को जनवितरण प्रणाली से संबंधित अनुज्ञप्ति सं०-13/2010 को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति को संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराते हुए मूल अभिलेख निम्न न्यायालय को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त

-सह-

जिला दण्डाधिकारी,गिरिडीह

उपायुक्त

उपायुक्त

-सह-

जिला दण्डाधिकारी,गिरिडीह